RAJYA SABHA

Wednesday, the 7th May, 1997/17 Vaisakha, 1919 (Saka)

The House met at eleven of the clock. eputy Chairman in the chair.

ANSWERS TO QUESTIONS

The questioner (Shri K.M. Khan) sent. For answer vide col....Infra]

ning New Post Offices in the villages of Bihar

442. SHRI S.S. AHLUWALIA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the target set for opening new post offices in the villages of Bihar during the Eighth Five Year Plan;

(b) the new post offices actually opened in the State during that Plan period against the target;

(c) the new post offices proposed to be opened in the State during 1997-98; and

(d) the target set for opening new post offices in the State during the 9th Five Year Plan and the Strategy Government propose to adopt to achieve the target?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया): (क) बिहार के गांवों में 183 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य था।

(ख) उपर्युक्त (क) में वर्णित लक्ष्य की तुलना में बिहार में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 183 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोले गए।

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान राज्य में 40 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 5 विभागीय उप डाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समूचे देश में 2500 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 250 विभागीय उप डाकघर खोलने का लक्ष्य है। तथापि, डाक सर्किलवार लक्ष्य प्रतिवर्ष वार्षिक योजना स्कीमों के अंतर्गत आबंटित किए जाते हैं और मानदंड संबंधी औचित्य होने और संसाधन उपलब्ध रहने पर ही मंजूर किए जाते हैं। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित कार्यनीति अपनाई जाएगी:—

(i) डाकघर खोलने के प्रस्तावों को शीघ्रतापूर्वक तैयार करना।

(ii) वित्त तथा मैनपावर के संबंध में आवश्यक संसाधनों की प्राप्ति के लिए अंतः मंत्रालयी परामर्श।

उपसभापति: आपका मंत्रालय बदल गया है क्या?

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया: ड्यूटी दे रहा हूं।

श्री एस०एस० अहलुवालिया: उपसभापति महोदया, मंत्री महोदय से मैंने जो सवाल पूछा था उसका सही-सही उत्तर नहीं आया। मैं जानना चाहूंगा कि बिहार के कामगार लोग, मजदूर लोग सारे भारत के कोने-कोने में काम करते हैं और खासकर के पंजाब, हरियाणा, बम्बई, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा सब जगह काम करने जाते हैं और यह गांव के लोग हैं। इन लोगों को अपने गांव से, अपने आत्मीयजनों के साथ में सम्पर्क स्थापित करने के लिए जो जरूरत पड़ती है डाकखाने की, मनिआर्डर के माध्यम से पैसे भेजने की, पर आज तक यह पूरा नहीं हो सका है कि बिहार के हर गांव में यह चीजें उपलब्ध हो सकें। महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि कब तक आप बिहार के हर गांव में पोस्ट आफिस या सब-पोस्ट आफिस लगा देंगे, ताकि बिहार के यह मजदूर जो बाहर काम करते हैं यह अपने रिस्तेदारों के साथ, अपने परिवारीजनों के साथ में सीधा सम्पर्क पोस्ट आफिस के माध्यम से कर सकें?

श्री बलन्वत सिंह रामूवालिया: महोदया, हमारे माननीय सदस्य ने बहुत वाजिब मुश्किल का जिक्र किया है, जो लोग बिहार से अन्य प्रदेशों में जाकर रोटी-रोजी के लिए काम करते है जिनको अपनी आमदनी अपने मां-बाप, अपने बच्चों के लिए भेजनी होती है। इसलिए आपको सुनकर के खुशी होगी कि सरकार बिहार में चूंकि यह लोग गांव से ही जाते हैं इसलिए गांव में ज्यादा पोस्ट आफिसेज खोलने के लिए यत्नशील है। जैसे अब तक 11063 पोस्ट आफिसेज, सब-पोस्ट आफिसेज, ब्रांच पोस्ट आफिसेज यह बिहार के गांवों में ही खोले गए हैं, जबकि बिहार के शहरों में वह 726 हैं। तो हम बिहार के गांवों में जो गांव के लोगों की जैसा माननीय सदस्य ने फरमाया हम उस पर ध्यान दे रहे है।

श्री एस०एस० अहलुवालिया: महोदया, बिहार में देवघर में एक ऐसा पोस्ट ऑफिस है सतसंगनगर, जो

भारत के किसी भी पोस्ट ऑफिस से मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा मनीऑर्डर रिसीव करता है। सतसंगनगर सिर्फ एक आश्रम है जिस आश्रम में सारे भारत से लोग अपना दसवांश अर्थात अपने गुरू के नाम पर पैसा भेजते है। सबसे कम रुपये की संख्या और सबसे ज्यादा रुपये की संख्या में वहां डीलिंग होती है। उसकी परम्पराओं को या उस पोस्ट ऑफिस के काम को मद्देनज़र रखते हुए हमारा जो मजदूर है जो बिहार से बाहर खासकर पंजाब, हरियाणा और बम्बई में रहता है, वह जब अपना पैसा भेजता है तो उसको बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। कई-कई महीने लग जाते है। क्योंकि आपके यहां जब उस पोस्ट ऑफिस में पैसा पहुंचता है, वहां के इम्पलाइज़ उस पैसे से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं और जब दूसरा पैसा आ जाता है तो उसको भेजते हैं। ऐसी बहुत सारी कम्पलेंट्स आपके पास आयी हैं। क्या आपने सतसंगनगर के उस पोस्ट ऑफिस को मद्देनज़र रखकर जहां पर चोरी की शिकायतें कम हैं, और दूसरे पोस्ट ऑफिसों में सुधार लाने की कोशिश की है?

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया: माननीय उपसभापति महोदया, एक तो मैं माननीय सदस्य को रिकवैस्ट करता हूं कि आपने जो अभी देवधर में सतसंगनगर पोस्ट ऑफिस का मामला और इम्पलॉइज़ की तरफ से, जो लोग बाहर काम करते हैं उनके द्वारा भेजे गये धन के दुरूपयोग का मुद्दा उठाया है, उसे हम बहुत गंभीरता से लेते हैं और 15 दिनों के अंदर पूरी इन्क्वायरी करवाकर जो भी दोषी होगा वह मैं आपके माध्यम से सदस्य महोदय को बता दूंगा।

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: सदन को बता दें।

उपसभापति: 15 दिन के बाद सदन नहीं होगा इसलिए आपको बता देंगे, फिर सदन को भी मालूम हो जाएगा।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया: दूसरी बात जो आपने कही है कि उस पोस्ट ऑफिस के मुताबिक दूसरी जगह भी काम करेंगे तो मेरी गुजारिश है कि एक तो जो आपने कहा है कि सभी गांवों में पैसा नहीं पहुंचता है तो हमने एक ऐसा सिस्टम इवाल्व किया है जिससे कुछ समय की देरी तो हो सकती है, हफ्ते-दस दिन की देरी हो सकती है लेकिन बिहार में सभी गांवों में मनीऑर्डर के पैसे पहुंचाने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त जो आपने कहा है कि दूसरे पोस्ट ऑफिसिस में हम उसके मुताबिक चलेंगे, इस पर हम पूरी हमदर्दी से कोशिश करेंगे क्योंकि यह तो फायदेमंद चीज़ है।

श्री नगेन्द्र नाथ ओझा: उपसभापति महोदया, इसी से संबंधित मेरा केवल एक सवाल है और वह यह है कि जो चालू व्यवस्था है, नये पोस्ट ऑफिस की बात छोड़ दीजिए जो चालू व्यवस्था है, क्या उसमें सुधार के बारे में मंत्री जी बता सकते हैं कि उसमें कोई सुधार करेंगे? जैसे बिहार का एक बक्सर इलाका है जहां मात्र वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर पत्र पहुंचने में हफ्ते जाते हैं। बक्सर में जो रेलवे मेल सर्विस की व्यव वह ऐसी है कि संडे को जो डाक दिल्ली की बिहार जाती है, वह पटना पहुंचती है 125 कि और पूर्व में, और सोमवार को फिर वह बक्सर किलोमीटर पश्चिम लौटकर आती है। इसी तर कलकत्ता से जो पत्र बक्सर के लिए चलता है, वह को मुगल सराय पहुंचता है जो बक्सर से किलोमीटर से ज्यादा पश्चिम में है। दिल्ली से यह व्यवस्था है। इसी तरह बलिया जो बक्सर से सिर्फ गंगा के उस पार है, वहां गांव में बक्सर से पत्र पहुंचने में, जहां उस इलाके के रिश्तेदार हैं, वह पत्र मुगल सराय जाएगा और फिर वहां से घूमकर ढाई सौ किलोमीटर की यात्रा करके पहुंचता है। इस बारे में इस विभाग का ध्यान आकृष्ट किया गया था और यह बात छह-सात महीने पूर्व की है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी हाउस को आश्वस्त करेंगे कि जहां लचर व्यवस्था है उसमें सुधार के लिए कुछ कदम उठाये जायेंगे?

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया: माननीय उपसभापति महोदया, यह सरकार है ही किस काम के लिए अगर सुधार ही न कर सके।

उपसभापति: एक्चुअली उनका मंत्रालय तो वेलफेयर का है।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया: माननीय उपसभापति जी, माननीय सदस्य जो फरमा रहे है, उन्होंने यह नहीं कहा है कि सुधार नहीं हुआ है। वह तो असल में यह कह रहे हैं कि सुधार की गति धीमी है और हम उसको तेज करेंगे।

श्री एस॰एस॰ सुरजेवाला: मैडम शुक्रिया। महोदया, मंत्री जी ने डी भाग के उत्तर में यह बताया है कि पूरे देश में नौवीं पंचवर्षीय योजना में ढाई हजार एक्सट्रा डिपार्टमेंटल पोस्ट आफिसेज और ढाई सौ डिपार्टमेंटल पोस्ट आफिसेज खोलने का लक्ष्य था। कितने खोले गये है यह तो इन्होंने नहीं बताया। साथ ही इन्होंने उन पोस्ट आफिसेज को खोलने के लिए नार्म्स बतायें हैं और जस्टिफिकेशन एंड एवैलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज ये दो

ग्राउण्ड दी है।

मैडम, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह बात ठीक नहीं है कि इन दोनों शब्दों का इनके डिपार्टमेंट के लोग अपनी मर्जी से गलत इस्तेमाल करते हैं? सच बात यह है कि वे सारे वीम्स पर खोलने लग रहे हैं और जहां पर नहीं खोलने हैं वहां पर भी उनके वीम्स की बात है। मैं एक उदाहरण देता हूं। जींद जिले में एक कालवन नामक गांव है उसमें दस हजार की आबादी है, लड़के-लड़कियों के लिए हाई स्कूल है, बैंक है, सब कुछ है और वहां पर एक आदमी पोस्ट आफिस का होता था, वह वन मैन पोस्ट आफिस था, उसको 1990 में बदल करके एक ऐसे गांव में लगा दिया जिसकी आबादी पन्द्रह सौ है। पिछले पांच सालों में मैंने 10 चिट्ठियां मंत्रियों को लिखीं और 10 चिट्ठियां महकमे वालों को लिखीं लेकिन उधर से एक ही जवाब आ जाता है कि देख लिया, जस्टिफिकेशन नहीं है। अब मैं कृपया करके यह चाहूंगा कि यह जस्टिफिकेशन और जो आपकी एविलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है इसको आप डिफाइन करवा दीजिए जिससे कि जहां पर जस्टिफिकेशन है वहां पर पोस्ट आफिसेज खुल सकें। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि आठ-दस हजार की आबादी वाले गांव में जस्टिफिकेशन है या पन्द्रह सौ की आबादी वाले गांव में जस्टिफिकेशन है। इस तरह का कोई एक केस नहीं है। मैंने केवल मिसाल के तौर पर यह बताया है। मंत्री महोदय ये जो आपके अधिकारी हैं इनके लिए आप कोई ऐसा कायदा बनाइये, इनके लिए कोई ऐसे नार्म्स होने चाहिएं जिनके आधार पर आप उनसे जवाब मांग सकें। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपने जो नाइंथ फाइव ईयर प्लान में ढाई हजार व ढाई सौ का टारगेट रखा वह पूरा हो गया है या अभी पोस्ट आफिसेज खोलने बाकी हैं?

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया: माननीया उपसभापति जी, असल में माननीय सदस्य का गुस्सा कालवन गांव का है।

उपसभापति: किसका है?

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया: जींद जिले के कालवन गांव का है।

उपसभापति: देखिए कालवन गांव की बात I won't permit because this question is specific to Bihar. You can't go on like this because there will be hundreds and thousands and millions of post-offices in our villages. We have other questions also. अगर आपसे बिहार के बारे में पूछते हैं या पालिसी मैटर के बारे में पूछते है तो प्लीज आन्सर दीजिए।

श्री एस०एस० सूरजेवाला: मैडम, मैंने किसी गांव के बारे में नहीं पूछा है, मैंने पालिसी मैटर के बारे में पूछा है। इन्होंने नेशनल लेवल की बात कही है, उसके बारे में मैंने पूछा है कि आपकी जस्टिफिकेशन और एजिलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के मायने क्या हैं? और क्या यह वायलेंट नहीं हो रही है? यह मेरा सवाल है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mantriji, Postal Department is a very big department. This question is specific to Bihar. If any hon. Member wants to put a question relating to Bihar, agreed; otherwise, there are twenty more questions on different subjects. I would like those questions to be answered. Let him answer now.

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया: उपसभापति महोदया, हालांकि आपने निर्णय दे दिया है कि बिहार के बाहर की बात न की जाये। फिर भी मैं कालवन गांव को दर्पण मानकर एक्सेप्ट करता हूं कि त्रुटियां हैं, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं लेकिन उसमें सरकार की नीयत में कोई त्रुटि नहीं है। हमने जो स्पेसिफिकेशन ले-डाउन की हैं उनका फायदा सदस्यों को उठाना चाहिए, एक मेजरिंग यार्ड आपको दे दिया, आपको पैमाना हमने दे दिया, अगर उसमें फिट नहीं होता है तो आपको हमें दोषी ठहराने की अन-चैलेन्जड अपोरचुनिटी है और उसके मुताबिक हम जो कुछ हो सकेगा, हम करेंगे।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Is it Bihar or U.P.? If it is any other State I will not permit because I have a number of other questions.

श्री नरेन्द्र मोहन: माननीय उपसभापति, मंत्री जी ने बड़े सरल स्वभाव से बिहार के मामले में अपने जवाब दिये हैं? उन्होंने कहा है कि त्रुटियां हो सकती हैं लेकिन नीयत में त्रुटियां नहीं है? आपके मंत्रालय की एक नीति जो सदन में घोषित की गई है कि देशभर में जितने गांव हैं उनमें शीघ्र ही पोस्ट आफिस खोल दिये जायेंगे। कम से कम वन मैन... पोस्ट आफिस खोल ही दिया जायेगा। साढ़ पांच लाख गांव हैं। मैं उनकी बात नहीं करता, मैं बिहार की बात कर रहा हूं। क्या आप यह बता सकेंगे कि बिहार में जो भी गांव है क्या हर गांव में आपने वन मैन पोस्ट आफिस खोल दिया है। जहां तक मेरी

जानकारी है अभी आपने कहा था कि सारे बिहार में डाकखाने खोल दिये गये हैं, ऐसी स्थिति नहीं है बल्कि सच बात यह है मंत्री जी मैं आपकी जानकारी के लिए यह बता रहा हूं कि पिछले मंत्री जी ने बताया था कि बिहार की पंचायतों से कहा गया कि वे सहयोग करें ताकि वहां के गांवों तक चिट्ठियां पहुंच सकें। अब आपकी नीति क्या है, वास्तविकता क्या है? योजना आयोग ने रिपोर्ट में कहा कि पंचायतों से सहयोग लेकर डाकखाने खोलने की बात कही गई थी लेकिन उसमें सरकार को सफलता नहीं मिल रही है। कृपा करके स्थिति स्पष्ट करें।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया: मैंने यह नहीं कहा कि बिहार के सभी गांवों में डाकखाने खोल दिये हैं। मैंने यह कहा था कि सभी गांवों में...।

श्री नरेन्द्र मोहन: आप कृपा करके यह बता दें।

उपसभापति: बोलने दीजिये। वे अभी पूरा करेंगे। नरेन्द्र मोहन जी, लैट हिम स्पीक।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया: नरेन्द्र मोहन जी, मैंने तो यह अर्ज की थी कि जो टोटल विलेजेज हैं, हमने उनमें से बिहार के 1,36,237 रूरल एरियाज का क्लेम बनता था उसमें से केवल 11,063 ही खोल सके। जब श्री अहलुवालिया जी ने कहा कि आप गांवों की उपेक्षा कर रहे हैं तब मैंने निवेदन किया था कि गांव में तो हमने 11,063 और शहरों में 726 किये हैं। यह मैंने अर्ज की थी। अब आप जी ने कहा कि गांवों की पंचायतों का इन्वॉल्व करके कुछ आगे बढ़ने का यत्न किया था। वह हमने खुशी से नहीं किया। हमारी मजबूरी यह थी कि हमने जितने प्रोपोजल नये डाकखाने खोलने के भेजे फाइनेन्स मिनिस्ट्री ने रिजेक्ट कर दिये। अब फाइनेन्स डिपार्टमेंट रिजेक्ट कर दे तो हाथ पर हाथ रखकर तो बैठा नहीं जा सकता, कुछ तो करना होगा। फाइनेन्स की भी मजबूरी रही होगी। उनकी मजबूरी है तो हमारी आपसे मजबूरी है।

श्री नरेन्द्र मोहन: मेरे सवाल का जवाब नहीं आया।

उपसभापति: देखिये, मामला मजबूरी का हो गया है। *(Interruptions)* Mr. Narendra Mohan, no. I have not identified you.

Security for Delhi Police Officials

*443. DR. RANBIR SINGH:†
SHRI RAM NATH KOVIND:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some Police Officers of Delhi have been provided security personnel without approval of protection Review Samiti of the Ministry;

(b) whether Government propose to take action against those officials who are responsible for providng security personnel without approval of competent authority; and

(c) if so, the details thereof; and if not, the reasons for such misuse?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI INDRAJIT GUPTA): (a) Yes Sir.

(b) and (c) Delhi Police have informed that they have provided such security to 5 Delhi Police Officers who are handling sensitive duties and are required to take stringent action against criminals and the underworld elements. This security has been provided keeping in view the threat perceptions in their cases. These cases will be got reviewed and further action will be taken on the basis of fresh threat assessment in their cases.

डा० रणबीर सिंह: मैडम, ये बड़ा प्वाइन्टेड क्वेश्चन था।

(a) Whether it is a fact that some Police Officers of Delhi have been provided security personnel without approval of Protection Review Samiti of the Ministry;

इसका जवाब यस है। दूसरा भी बहुत प्वाइन्टेड क्वेश्चन था।

(b) Whether Government propose to take action against those officials who are responsible for providing security personnel without approval of competent authority.

जिसके जवाब में, इनका जवाब नहीं है। क्या एक्शन

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Ranbir Singh.